पर जनता का राज न आकर राज्यपाल का शासन आ जाता है। राज्यपाल महोदय ने एक जीओ जारी किया और पैंतीस हजार रुपये से हटाकर बीड़ी की उजारत 27 रुपये हजार कर दी। यह बड़ा जालिमाना खेल है, यह बड़ा निन्दनीय काम है और इसकी निन्दा होनी चाहिये, सदन में भी होनी चाहिये और सरकार को भी इसे देखना चाहिये। क्या किसी राज्यपाल को यह हक हासिल होगा कि वह भूखें लोगों के मुंह से लुकमा निवाला और रोटी छीनने का काम करेगा, अनेकों जिस्मों से खाल उतारने का काम करेगा? लिहाजा मेरी मांग और चाहना यह है कि बीड़ी मजदूरों की इस समस्या पर कोई समिति बननी चाहिये और एक नेशनल वेज बोर्ड, जैसा टेक्सटाइल और शुगर का है इसी तरह का बोर्ड बीड़ी मजदूरों के लिए भी बनना चाहिये। मजदूरों के साथ जो अन्याय हुआ है इसके लिए जी॰ओ॰ वापस होना चाहिए और बीड़ी मजदूरों की उजरत बढ़नी चाहिए।

गरीबे शहर के तन पर लिबास बाकी है,
अमीरे शहर के अरमां अभी कहां निकले।

बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री महेश्वर सिंह: ऐसा भी कहें कि ऐसे राज्यपाल को बरखास्त किया जाना चाहिए।

उपसभापति: राज्यपालों का बरखास्त करना हमारा काम नहीं है। बीड़ी वरकर्स तमाम जगह अन-आर्गनाइज्ड सेक्टर में हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं। उनके लिए कुछ होना चाहिए।

I know about this. They have to be taken care of.

श्री सुन्दराजन, लोगों को ट्रेन पकड़नी है। इसलिए जरा जल्दी से बोलिए।

Need to ensure the safety of people living around the L.P.S.C. Plant of I.S.R.O. in Thirunelveli District of Tamil Nadu

SHRI P. SOUNDARARAJAN (Tamil Nadu): Madam Deputy Chairman, as I rise to make my maiden speech, I record my gratitude to Dr. Puratchi Thalaivi, the former Chief Minister of Tamil Nadu, who has sent me to this august House.

Madam, I feel it my duty to bring to the notice of the Government a grave injustice meted out to the people of Mahendragiri-panakudi area of Thirunelveli Kattabomman district in Tamil Nadu.

The Liquid Propulsion System Centre of ISRO is situated at Mehandragiri in Thirunelveli Kattabomman district of Tamil Nadu. When it was being set up 16 years ago,.people of that area objected to it fearing displacement and also health hazards by the plant. At that time, the Government and also the ISRO authorities promised jobs at the LPSC plant for the families whose lands were acquired. The people were also assured of safety to their health and lives. After giving all these assurances, about 1500 acres of land was acquired by the Government from over 700 poor farming families of Kaval Kinaru, Lappai Kudiiy-uruppu, Panakudi, Kumarapuram, Krish-napuram and Avaraikuiam villages at a throw-away price of nine rupees and fifty five paise per cent. But today, after 16 years, the people who were displaced feel cheated by the Government.

So far, not a single project-affected person has been given employment in the LPSC plant. Members of the affected families have not been given even Class-C or Class-D posts. The promised housing units have not been provided. The poor people who have given their lands have nowhere to go for their livelihood. After having run from pillar to post, they have resorted to agitation. Since I come from that region, I know the troubles the people have been facing all these years.

Madam Deputy Chairman, last year a highly dangerous Integrated Liquid Hydrogen plant was commissioned in the unit exposing the people of the area to a great danger. Now, a residential complex for the scientists and staff of the LPSC is proposed to be constructed at Nagcrcoil, 26 kilometres away from the plant. This decision to have staff quarters away from the plant site has increased the fear of the people regarding the safety of the plant.

Madam, the people of Mahendragiri area have no means of livelihood, no place to stay and they are living in the grip of fear, always thinking that something like the Bhopal gas tragedy would take place. Therefore, I demand firstly that at least one member of each

project-affected family be given employment in the LPSC plant. They may be considered for Class-Ill and Class-IV non-technical posts. If it is not possible to provide jobs to all the affected families, the left-out families should be given compensation by paying them the prevalent price for their lands which is over Rs. 2,000 per cent.

Secondly, the staff quarters should be constructed within Mahendragiri-Panakudi limits so as to instil confidence in the minds of the people.

Madam, a white paper should be issued regarding the integrated liquid hydrogen plant in order to remove fears from the minds of these people.

Thirdly, the displaced families should be provided residential accommodation adjoining the staff quarters by the Government. Since these people have been agitating for a long time, I therefore appeal to the Central Government, Madam Deputy Chairperson, to intervene in the matter immediately and provide what is due to them. Thank you, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You have raised a very important issue in your first speech. Congratulations.

Worsening Cotton. Position Particularly in Gujarat

श्री अनंतराय देवशंकर दवे (गुजरात): महोदया, मैं इस स्पेशल मेंशन के जरिए इस सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर खींच रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले यहां मिनिस्टर साहब ने शुगर बिल पेश किया था। वे रिपील करवाना चाहते थे। उस वक्त उन्होंने बयान भी दिया। जो काम इस सरकार को नहीं करना चाहिये वह काम सरकार कर रही है। जो काम करना चाहिये वह सरकार नहीं कर रही है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि गुजरात में और देश के करीब 9 राज्यों में काटन ग्रोअर्स की हालत बड़ी गंभीर है। दिन प्रति दिन ये किसान मांग कर रहे हैं कि हमें काटन एक्सपोर्ट करने दीजिए। देश में उसका उत्पादन पूरी मात्रा में है। सरकार की ओर से ऐसा जवाब दिया जा रहा है कि डोमेस्टिक जो हैंडलूम्स हैं मिल्स हैं उनका क्या होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि आज हमारे पास 145 लाख बेल्स प्रोड्यूस हुई है। हमारी जो देश की डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है वह करीब 112-115 के बीच में है। बाकी मात्रा में काटन आज देश में—गुजरात और अन्य 9 राज्यों में पड़ा है। किसानों को बिजली नहीं मिलती है, खाद नहीं मिलता है। मिलता है तो बडे दाम पर मिलता है लेकिन दिन प्रति दिन काटन का भाव नीचे जा रहा है। किसान की हालत बहुत खराब है। ओ॰ जी॰ एल॰ कर देना चाहिये। उससे देश को रेवेन्यू भी मिलेगा, फारेन एक्सचेंज भी मिलेगा। चारों ओर से डिमांड हो रही है लेकिन सरकार के कान पर यह बात नहीं आ रही है। समझ में नहीं आता है कि जो काम नहीं करना चाहिये, शुगर वाला, वह कर रही है और जो काम करना चाहिये वह नहीं कर रही है जबकि किसान मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है क्योंकि उनको बिचौलिए, जो मिडिलमैन हैं वे दिखाई दे रहे हैं। अभी भाव नीचे दबे हैं। मिडिल परसन किसानों के पास से नीचे दाम पर ले लेंगे। किसानों के घर से निकल जाएगा तब एक्सपोर्ट की बात आएगी, मदद आएगी। एक्सपोर्ट तब खुलेगा जब फायदा उन बिचौलियो को होगा। हमारे देश में लोगों के पास कपास पूरी संख्या में है, पूरी मात्रा में है क्योंकि कितनी ही मिल्स गुजरात में आज बंद हो गयी हैं। हैंडलूम के लिए जो कपास हमको चाहिये वह कपास हमारे पास है। उसमें भी दो तीन किस्म का काटन होता है—छोटे तार वाला और बड़े तार वाला। जो छोटे तार वाला काटन है जापान में उसकी बड़ी डिमांड है। वह ओ॰ जी॰ एल॰ कर देना चाहिये। लास्ट इयर भी 5 हजार बेल्स हमने एक्सपोर्ट किए थे। अभी हमने पाबंदी लगा दी है। यह समझ में नहीं आता है। मैंने कल एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात की। एग्रीकल्चर मिनिस्टर एक ओर काटन ग्रोअर्स को बढ़ावा देने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, काटन का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और दूसरी ओर वे कहते हैं कि हमारे पास नहीं इसके लिए आप कामर्स मिनिस्ट्री में जाइए। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं कि किसान को आप बचाइए। किसान परेशान है। जिन-जिन स्टेट्स में काटन ग्रोअर्स परेशान हैं उनके लिए आप खुद सोचें। आप कहते तो हैं कि हमारी सरकार किसानों की सरकार है लेकिन आप किसानों के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। आज किसानों की मदद करने के लिए काटन को ओ॰ जी॰ एल॰ में करिए चाहे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगाइए। लेकिन आज अगर ओ॰ जी॰ एल॰ में वह नहीं जाएगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा तो किसान खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, वह कभी भी काटन अपने खेत में नहीं बोएगा। फिर वही समस्या खड़ी हो जाएगी। बिचौलियों को मत बचाएं। यह सरकार कोई कदम उठाए । गुजरात और दूसरे 9 राज्यों के किसानों की यह डिमांड है। वहां की सरकारों ने भी